बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 138

वित्तीय स्पष्टता की आवश्यकता

केंद्र सरकार ने राजस्व के मोर्चे पर बेहतर हुई स्थिति का फायदा उठाते हुए चालू वर्ष के लिए कम राजकोषीय घाटा दर्शाया है। चालू वित्त वर्ष में घाटे को सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 4.9 फीसदी के बराबर रखने का लक्ष्य तय किया गया है जबकि अंतरिम बजट में यह लक्ष्य 5.1 फीसदी का था। सरकार ने 2021 में घोषणा की थी कि घाटे को 2025-26 तक कम करके जीडीपी के 4.5 फीसदी के स्तर तक लाया जाएगा। सरकार अगले वर्ष इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अग्रसर है। इस संदर्भ में वित्तीय बाजारों और विश्लेषकों को उम्मीद थी कि केंद्रीय बजट में मध्यम अवधि के लिए संशोधित राजकोषीय पथ घोषित किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि 2026-27 से सरकार राजकोषीय घाटे का प्रबंधन इस प्रकार करेगी कि केंद्र सरकार का कर्ज जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कम होता रहेगा।

बजट के बाद मीडिया से (इस समाचार पत्र समेत) बात करते हुए वित्त मंत्री ने तथा वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि सरकार खुद को खास लक्ष्यों में उलझाने के बजाय बदलते आर्थिक हालात के अनुसार कदम उठाना चाहती है। बहरहाल, सरकार को सलाह होगी कि वह और अधिक स्पष्टता प्रदान करे। साफ कहा जाए तो कर्ज पर ध्यान केंद्रित करना उचित है। वित्तीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम में उम्मीद जताई गई थी कि मार्च 2025 तक सामान्य सरकारी ऋण जीडीपी के 60 फीसदी तक सीमित रहे और केंद्र सरकार के ऋण का अनुपात 40 फीसदी रहे। बजट दस्तावेजों में राजकोषीय नीति को लेकर जो वक्तव्य दिए गए हैं उनके मुताबिक राजकोषीय घाटा केवल एक परिचालन लक्ष्य है।

चालू वर्ष में केंद्र सरकार कर्ज के स्तर के जीडीपी के 56.8 फीसदी रहने के अनुमान को देखते हुए अंशधारकों के लिए यह महत्त्वपूर्ण है कि उन्हें पता रहे कि सरकार अगले करीब पांच साल में किस लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम कर रही है। यह जानना भी अहम होगा कि इस तय अवधि में कर्ज का वांछित स्तर पाने के लिए राजकोषीय घाटे को किस स्तर तक सीमित रखना होगा। ऐसे में मध्यम अवधि में घाटे का स्तर और कर्ज दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होंगे। विकास के इस मोड़ पर जब सरकार और निजी क्षेत्र दोनों को निवेश के लिए धन जुटाने की आवश्यकता है, पारदर्शी और नियम आधारित राजकोषीय ढांचा मददगार साबित होगा। एफआरबीएम अधिनियम के पीछे भी यही विचार रहा है। एक नियम आधारित राजकोषीय ढांचा रेटिंग एजेंसियों के लिए भी मददगार होगा क्योंकि वे उस आधार पर भारत का आकलन कर सकेंगी।

राजकोषीय घाटे की भरपाई करने की अर्थव्यवस्था की क्षमता भी बातचीत से नदारद है। विशुद्ध पारिवारिक वित्तीय बचत 2022-23 में जीडीपी के 5.3 फीसदी के साथ कई दशकों के निचले स्तर पर आ गई। अगर यह जीडीपी के 7.5 फीसदी के अपने पिछले दशक के औसत स्तर पर वापस भी आ जाती है तो भी यह पूरी तरह सरकारी बजट घाटे की भरपाई में खप जाएगी और निजी क्षेत्र के लिए कुछ नहीं बचेगा। यह बात भी सभी जानते हैं कि निजी निवेश में बेहतरी मध्यम से लंबी अवधि के दौरान टिकाऊ उच्च वृद्धि हासिल करने के लिए जरूरी है। एफआरबीएम अधिनियम में राजकोषीय घाटे का वांछित स्तर भी अर्थव्यवस्था में वित्तीय बचत की उपलब्धता पर आधारित था। लंबे समय तक घाटे में इजाफा होने पर यह जोखिम होता है कि निजी निवेश बाहर हो जाए। ऐसे में दीर्घावधि की संभावनाएं प्रभावित होती हैं। सरकार को एक संशोधित राजकोषीय ढांचे की आवश्यकता है जो आर्थिक वृद्धि, ऋण के स्थायित्व और अर्थव्यवस्था में वित्तीय बचत के साथ सुसंगत हो।

अजय मोहंती

आम बजट: भाजपा को 'बेस' पसंद है

इस बजट में किसी चीज की कमी है, तो वह है आर्थिक संदेश। इसमें सुधारों को लेकर कोई विस्तृत बयान नहीं है, निजीकरण, विनिवेश, बड़ी कर कटौती, प्रोत्साहन, विनियमन आदि का भी कोई उल्लेख नहीं है।

समझ की दृष्टि से सरलता के लिए तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संक्षिप्त अक्षरों के प्रति लगाव से संकेत ग्रहण करते हुए हम इस बजट को 'बेस' प्रभाव वाला बजट कह सकते हैं। या फिर सलमान खान की फिल्म सुल्तान के एक गाने से प्रेरणा लेते हुए कहा जा सकता है कि 'भाजपा को बेस पसंद है'। यहां बेस से तात्पर्य है बिहार, आंध्र प्रदेश, सोशलिज्म (समाजवाद) और एंप्लॉयमेंट (रोजगार)।

इससे पहले कि हम 2024 के बजट के राजनीतिक संदेश की गहराई में जाएं, हमें इस बात को समझना होगा कि राजनीति को कभी अर्थव्यवस्था से अलग नहीं किया जा सकता है।

बजट के विभिन्न वित्तीय, राजकोषीय और कराधान संबंधी पहलुओं पर काफी कुछ लिखा और पढ़ा जा चुका है। यह पूरे वर्ष में सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे अहम राजनीतिक वक्तव्य होता है। यह राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बारे में अपनी बात ही नहीं कहता है बल्कि यह भी दिखाता है कि सरकार किस दिशा में जा रही है और वह कहां से आ रही है। इस वर्ष के बजट में दूसरी वाली बात कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है।

राष्ट्र की बात
शेखर गुप्ता

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण को दोबारा सुनिए। पहले 25 मिनट के दौरान उन्होंने केवल आंध्र प्रदेश और बिहार की बात की है। अगर आपको लगता है कि यह समय बहुत ज्यादा है (पूरे बजट भाषण का करीब एक चौथाई समय दो राज्यों पर केंद्रित रहा) तो आप राजनीतिक संदेश की अनदेखी कर रहे हैं। मोदी सरकार ने अब तक जो दस बजट पेश किए हैं वे भाजपा के बजट थे। यह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का पहला बजट है।

यही वजह है कि केवल इन दो राज्यों को इतना अधिक धन आवंटन किया गया है जबकि इनकी आबादी देश की कुल आबादी के 15 फीसदी से भी कम है। दोनों राज्यों का अतीत में विभाजन हो चुका है जिससे उनके आकर्षक हिस्से अलग हो गए और दोनों विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे थे। किसी ने उनकी नहीं सुनी। परंतु अब इन राज्यों की 18 सीट (तेलुगु देशम की 16 और जनता दल यूनाइटेड की 12) के बिना राजग सरकार अल्पमत में होगी।

इन 25 मिनट और हजारों करोड़ रुपयों के वादों के अलावा भी कई महत्त्वपूर्ण वादे किए गए जिनमें मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे और आंध्र प्रदेश के पोलावरम में स्थित करीब-करीब रद्द मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट शामिल है। यानी पहला राजनीतिक वक्तव्य है आत्मस्वीकारः पहले के दो अवसरों की तरह इस बार गठबंधन सरकार है। हमने जिस 'बेस' का जिक्र किया है उसका बी और ए यही दोनों राज्य हैं।

अगर इस बजट में कोई कमी है तो वह है आर्थिक संदेश की। सुधारों को लेकर कोई व्यापक संदेश नहीं है, निजीकरण, विनिवेश का जिक्र नहीं, बड़ी कर कटौती नहीं, प्रोत्साहन या विनियमन का उल्लेख नहीं है। राजकोषीय अनुशासन के अलावा ऐंजल टैक्स समाप्त करने का सुधारवादी कदम उठाया गया है। हालांकि यह संभवतः बीते दो दशक का इकलौता ऐसा बजट है जिसमें सरकार द्वारा कारोबार में अपनी भूमिका कम करने का उल्लेख नहीं है। इसकी तुलना मोदी सरकार के उस वक्तव्य से कीजिए जब महामारी के बीच सुधारों के बीच कहा गया था कि सरकार कुछ सामरिक क्षेत्रों के अलावा हर कारोबार से बाहर रहेगी। अब वह विचार भुला दिया गया है।

प्राप्तियों के विभिन्न स्तंभों से इतर हमें विनिवेश के बारे में 50,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य का जिक्र मिलता है। साल दर साल मोदी सरकार विनिवेश लक्ष्य हासिल करने में पिछड़ती रही है। 2014 से अब तक इकलौता उल्लेखनीय निजीकरण एयर इंडिया का हुआ है। जबकि सरकार ने रिजर्व बैंक और सरकारी उपक्रमों से लाभांश के रूप में 2.9 लाख करोड़ रुपये मिलने का बजट अनुमान पेश किया है।

यह सरकार निजी क्षेत्र को लोगों को रोजगार देने के लिए लाखों करोड़ रुपयों का प्रोत्साहन दे रही है। ऐसा विभिन्न सब्सिडी और प्रोत्साहनों के जरिये किया जा रहा है। यह प्रक्रिया अपने आप में इतनी जटिल है कि इसके लिए दिल्ली में एक और 'भवन' के निर्माण को उचित ठहराया जा सकता है। निजी क्षेत्र के रोजगार निर्माण में यह सरकार का सबसे बड़ा हस्तक्षेप है।

वास्तव में क्या निजी कारोबारी केवल इसलिए किसी को रोजगार देते हैं कि सरकार उसकी लागत का कुछ हिस्सा वहन करेगी? कारोबार तब लोगों को काम पर रखते हैं जब उन्हें मुनाफा और वृद्धि नजर आती है। एक मुक्त बाजार और सुधारवादी अर्थव्यवस्था में सरकार अधोसंरचना, विनियमन तथा करों में कमी आदि की मदद से कारोबारों की सहायता करती है। यह एक किस्म की समाजवादी राज्य की अवधारणा है कि वह रोजगार के लिए प्रोत्साहन देकर लोगों को काम दिला सकती है।

हम आज के इस विश्लेषण की शुरुआत समाजवाद के 'स' से भी कर सकते थे। इस बजट का सबसे प्रमुख राजनीतिक संदेश यही है। आयकर दाताओं के निचले स्लैब के करदाताओं को सालाना 17,500 रुपये की मामूली राहत दी जाएगी। परंतु यूरोपीय शैली में अमीरों से अधिक कर वसूली की जा रही है। पूंजीगत लाभ कर में हर स्तर पर इजाफा किया गया है। इसको 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है। अल्पावधि के पूंजीगत लाभ कर को 15 फीसदी से बढ़ाकर 20 से 33 फीसदी तक किया गया है। संपत्ति पर होने वाले लाभ से इंडेक्सेशन को समाप्त कर दिया गया है। इसे अतीत की तिथि से लागू करना भी यूरोपीय शैली के समाजवादी कराधान का नमूना है।

इसमें सरकार समर्थित इंटर्नशिप योजना और नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देने की योजना (ये दोनों हमें कांग्रेस के समाजवादी घोषणापत्र में नजर आई थीं) को शामिल कर दें तो यह आसानी से कहा जा सकता है कि 11वें वर्ष में भाजपा ने हमारा सामना वापस एक कड़वे सच से करा दिया है। वह यह कि हमारी राजनीति में अन्य वैचारिक दलीलें चाहे जो हों, समाजवाद हमारा राष्ट्रीय द्विपक्षीय आर्थिक विचार है।

एक समय इस बात का बड़ा हल्ला था कि अगर भाजपा सत्ता में बड़े बहुमत से वापस आई तो यह संविधान की प्रस्तावना में आपातकाल के दौरान शामिल 'पंथ निरपेक्ष और समाजवादी' शब्द को जरूर हटाएगी। अब आप निश्चिंत होकर कह सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। यह बजट साबित करता है कि भाजपा स्वीकार करती है कि समाजवाद ही हमारे बेस का तीसरा अक्षर यानी 'एस' है।

रोजगार के नाम पर जितना धन देने की बात कही गई है वह भी बताता है कि यह उस राजनीतिक नेतृत्व का वक्तव्य है जिसने यह दिखाने में बहुत अधिक समय लगा दिया कि वह चुनाव में बहुमत से पीछे क्यों रह गया। यही वजह है कि बजट में भविष्य को लेकर उतनी खुशनुमा बातें नहीं की गई हैं। भाजपा का थिंक टैंक अभी भी यह सोचने में व्यस्त है कि गलती कहां हुई। ऐसा इसलिए ताकि आगे और नुकसान न हो। इतिहास की अन्य सरकारों की तरह इसने भी चुनौती सामने आने पर समाजवाद का रास्ता अपनाया है।

पुनश्चः 'बेस' का विचार डिप्टि के डिप्टी एडिटर (अर्थशास्त्र) टी.सी.ए. शरद राघवन ने दिया था। मैंने खुशी-खुशी उनसे यह उधार ले लिया।

बहुलवादी चुनाव व्यवस्था में जीत कितनी तर्कसंगत?

पिछले पखवाड़े में हमें यह अनुभव हुआ कि हमारी चुनाव प्रणाली बुनियादी रूप से कमजोर एवं अतार्किक हो सकती है। भारत, ब्रिटेन और अमेरिका में चुनाव क्षेत्र आधारित फर्स्ट-पास्ट- द-पोस्ट (एफपीटीपी) वोटिंग प्रक्रिया दो वास्तविक दलों वाले देशों जैसे अमेरिका में वास्तविक पसंद को कुछ अंश तक ही परिलक्षित करती है। अधिक बिखराव एवं विविधता वाली राजनीतिक व्यवस्था की स्थिति में यह प्रक्रिया अपना महत्त्व खोने लगती है। एफपीटीपी ऐसी चुनाव व्यवस्था है जिसमें जिस उम्मीदवार को अन्य सभी उम्मीदवारों से अधिक वोट मिलते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। विजयी उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसे कुल मतों का बहुमत यानी 50 प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त हुए हों।

उदाहरण के लिए ब्रिटेन के आम चुनाव में लेबर पार्टी ने 650 में 450 सीट जीत कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। यानी लेबर पार्टी को 60 प्रतिशत से अधिक सीट पर जीत मिली। मगर इतना भारी बहुमत हासिल करने के बाद भी पार्टी को केवल 33.8 प्रतिशत मत ही प्राप्त हुए। इस बीच, आव्रजन विरोधी नए दल रिफॉर्म पार्टी का प्रदर्शन मत प्रतिशत के लिहाज से शानदार रहा। इसके नेता नाइजल फराज को आखिरकार आठवें प्रयास में संसद पहुंचने का अवसर मिल गया। मगर 14 प्रतिशत मत पाने के बाद भी इस पार्टी को केवल 5 सीट मिलीं। वर्ष 2015 में यूनाइटेड किंगडम इंडिपेंडेंस पार्टी को 12 प्रतिशत से अधिक मत मिले थे, मगर उसके पाले में केवल एक सीट आई थी। सबसे शानदार सफलता मध्यमार्गी लिबरल डेमोक्रेट्स को मिली। उदारवादी लंबे समय से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग करते रहे हैं। वे ब्रिटेन में अस्तित्व में आने के बाद से तीसरे सबसे बड़े दल रहे हैं, मगर राजनीति में उनका विशेष दखल नहीं रहा है। वर्ष 2019 में हुए चुनाव में उनके नेता जो स्विंसन ने सबसे बड़े दलों के बराबर खड़ा होने का प्रयास किया था। उन्होंने स्वयं को संभावित प्रधानमंत्री के रूप में पेश करने का प्रयास किया और लगभग सभी चुनाव क्षेत्रों में दांव आजमाने पर ध्यान केंद्रित किया था। उदारवादियों ने अपना मत प्रतिशत चार आधार अंक जरूर बढ़ा लिया मगर उनकी सीट 12 से कम होकर 11 रह गईं। इसकी तुलना में 2024 में पार्टी ने जीत की अधिक संभावनाओं वाली 100 से कम सीट पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अपने सभी संसाधन वहां झोंक दिए और दूसरे दलों की तुलना में काफी पहले ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। पार्टी के नेता ने स्वयं को प्रधानमंत्री के रूप में पेश करने से परहेज किया और इसके बजाय कुछ विशेष मगर नीतिगत विषयों के लिहाज से महत्त्वपूर्ण सीटों पर ध्यान दिया। लिबरल डेमोक्रेट्स का मत प्रतिशत मात्र 0.6 प्रतिशत बढ़ा, मगर संसद में उनकी सीट छह गुना बढ़कर 72 हो गईं। यह पिछले कई दशकों में उनका सबसे उम्दा प्रदर्शन रहा है। इन बातों के बावजूद एफपीटीपी छोटे दलों के लिए चुनौती रहा है क्योंकि इतने ऐतिहासिक प्रदर्शन के बावजूद हाउस ऑफ कॉमन्स में उनकी सीट की हिस्सेदारी उनके मत प्रतिशत के मोटे तौर पर समतुल्य है।

नीति नियम
मिहिर शर्मा

ब्रिटेन के पड़ोसी देश फ्रांस में स्थिति काफी अलग है। वहां एक अप्रत्याशित एवं शुरुआती चुनाव में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से जुड़े मध्यमार्गी गठबंधन को सीट का काफी नुकसान हुआ। अंतिम परिणाम आने पर न वामपंथी, न ही मध्यमार्गी और न ही दक्षिण-पंथी (जो अप्रत्याशित रूप से तीसरे स्थान पर रहा) दलों को बहुमत मिला। फ्रांस में भी एफपीटीपी है मगर वहां दो चरणों में मतदान होता है। दूसरे चरण में केवल वे उम्मीदवार ही चुनाव लड़ने के पात्र होते हैं जिनका प्रदर्शन पहले चरण में मजबूत रहता है। इससे मतदाताओं को उम्मीदवारों की एक छोटी सूची में अपना मनपसंद उम्मीदवार चुनने में मदद मिलती है।

फ्रांस में लंबे समय तक एक दूसरे के कट्टर शत्रु रहे वामपंथी और मध्य मार्गी ने दूसरे चरण में अति चरमपंथी दलों को रोकने के लिए एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया। वामपंथी दलों के लगभग सभी मतदाताओं ने मध्यमार्गी उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान किया, जबकि मध्यमार्गी मतदाताओं के एक छोटे समूह ने वामपंथी उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान किया। पहले चरण में सबसे आगे चलने वाले अति चरमपंथी दलों को रोकने के लिए ऐसा करना जरूरी था, जो दूसरे चरण में तीसरे स्थान पर पहुंच गए। मगर यह प्रश्न काफी जटिल है कि चुनाव में 'जीत किसे मिली है' और इस पर अब भी बहस चल रही है।

कुछ मायनों में फ्रांस की चुनाव प्रणाली अमूमन रणनीतिक मतदान के जटिल प्रश्न को पारदर्शी और आसानी से समझ एवं चर्चा के लायक बना देती है। ब्रिटेन में लेबर और लिबरल डेमोक्रेट्स सीमित मतदान प्रतिशत के साथ मजबूत प्रदर्शन करते प्रतीत हुए हैं क्योंकि उनके मतदाताओं ने काफी सूझ-बूझ का परिचय दिया है। मतदाताओं के लिए यह स्पष्ट था कि कंजर्वेटिव पार्टी के खिलाफ किस उम्मीदवार के जीतने की प्रबल संभावना थी। लिबरल डेमोक्रेट्स का ऐसे क्षेत्रों में प्रचार अभियान बिल्कुल सरल था 'लिबरल डेमोक्रेट का उम्मीदवार यहां जीत रहे हैं'। यह इस बात का संकेत था कि उनके लिए मतदान करना पूरी तरह सुरक्षित था।

एफपीटीपी के उचित या अनुचित होने पर स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। केवल मत प्रतिशत को देखते हुए तो बिल्कुल किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। मतदान करने के लिए मतदाताओं के पास पर्याप्त सूचना है कि नहीं यह भी एक बड़ा सवाल है। भारत में यह कहना बहुत मुश्किल होता है कि किसी चुनाव क्षेत्र में कौन सा उम्मीदवार भारी पड़ रहा है। इसका मतलब है कि मतदाताओं के लिए यह समझना कठिन होता है, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां मुकाबला चौतरफा हो जाता है। इस कारण से दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में चुनाव-पूर्व गठबंधन भारतीय चुनाव की एक खास बात बन गई है।

आपका पक्ष

आसान नहीं चीन से वस्तुओं का आयात रोकना

भारत में जब से चीनी सामान आना शुरू हुआ है, तब से कितने ही छोटे-मोटे उद्योग धंधे या तो बंद हो गए या उन पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। चीन को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक भी किया था। भारत चीन से लगभग 8,000 से अधिक वस्तुओं का आयात करता है। चीन से आने वाली कई वस्तुओं का निर्माण भारत में आसानी से किया जा सकता है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। भारत अंतर-राष्ट्रीय नियम के तहत चीनी सामान पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। चीन से आर्थिक लड़ाई लड़ने में हमारे देश के नागरिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके लिए नागरिकों को चीनी सामान पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। इनमें बच्चों के खिलौने, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान तथा ऐप हैं।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

भारत चीन से 8,000 से अधिक वस्तुओं का आयात करता है लेकिन चीन से आने वाली कई वस्तुओं का निर्माण देश में किया जा सकता है

नदियों को स्वच्छ करने के लिए नीति में बदलाव जरूरी

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद भी नदियों के किनारों पर स्थित उद्योग धंधों में औद्योगिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ईटीपी) अपेक्षित मात्रा में नहीं बनाए गए हैं। इस हेतु 2018 में योजना बनी थी। नदियों के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण कल-कारखानों के जहरीले रसायनों को नदी में बेरोक-टोक के गिराया जाना है। प्रतिदिन यह औद्योगिक कचरा इन्हें विषैला बना रहा है। नदियों में फेंके जाने वाले कुल कचरे में लगभग 80 प्रतिशत शहरी होता है, जबकि 15 प्रतिशत औद्योगिक कचरा और बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में फेंका जाता है। शहरी कचरा नदियों के प्राकृतिक स्वरूप को नष्ट कर रहा है और औद्योगिक कचरा रासायनिक रूप से इनके पानी को जहरीला बना रहा है। प्रदूषण का दूसरा बड़ा कारण है-खेती में रासायनिक खादों और जहरीले कीटनाशकों का बेतहाशा प्रयोग। ये रसायन बारिश के समय बहकर नदी में पहुंच जाते हैं तथा नदी की पारिस्थितिकी को बिगाड़ देते हैं। अतः नदियों के किनारों पर स्थित खेतों में जैविक खाद का उपयोग जरूरी है। नदी में आकर मिलने वाले छोटे-बड़े नालों के किनारे 50- 50 मीटर तक सघन पौधरोपण कर और इन नालों का गंदा पानी नदी में नहीं मिले, इस हेतु बड़ी संख्या में स्टॉप डैम बनाने से इस स्थिति पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

उपभोग की मात्रा में संतुलन बनाने की आवश्यकता

फल और सब्जियों की मौसमी महंगाई अमूमन हर वर्ष बारिश के मौसम में बनी रहती है। यह महंगाई फल-सब्जियों की मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है। अपेक्षाकृत कम उत्पादन और मांग यथावत बनी रहने के कारण मौसमी महंगाई स्वाभाविक ही है। इस महंगाई से राहत के लिए हमें अपने उपभोग को सीमित करना चाहिए। अधिक महंगे फलों और सब्जियों की खरीद कम करेंगे तो मांग में कमी होने पर इनके मूल्यों में स्वाभाविक रूप से गिरावट आ सकती है।

रमेशचंद्र कर्नावट, उज्जैन

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को इस पद पर दो साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। इस अवसर पर वह शिक्षिका की भूमिका में नजर आईं और विद्यार्थियों से ग्लोबल वार्मिंग रोकने के तरीकों पर संवाद किया। मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय में नौवीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ संवाद किया और उन्होंने जल संरक्षण तथा अधिक पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया।

हिन्दुस्तान 1936 सत्य - सार्थक - सदैव

मिसाइल सुरक्षा

बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के निर्माण में भारत का आगे बढ़ना सुखद और स्वागतयोग्य है। यह देश के लिए खुशखबरी है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने बुधवार को 5,000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को नाकाम करने की क्षमता का सफल परीक्षण किया है। बुधवार सुबह से ही बालासोर, ओडिशा के समुद्री तट के आसपास के गांवों में बड़ी हलचल थी कि वैज्ञानिक कोई बड़ा प्रयोग करने जा रहे हैं। अनेक गांव खाली करा लिए गए थे, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के साथ ही उन्हें आर्थिक मुआवजा भी दिया गया था। बुधवार देर शाम ही यह स्पष्ट हुआ कि आसमान में उड़ती दुश्मन की मिसाइल को जमीन से मार गिराने की क्षमता का सफल परीक्षण किया गया है। यह भारत की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के दूसरे चरण की सफलता का अवसर है। मतलब जल्द ही, भारत अपने महत्वपूर्ण शहरों, ठिकानों के आसपास ऐसा मिसाइल सुरक्षा तंत्र स्थापित करेगा, जिससे दुश्मन की ओर से आ रही किसी भी खतरनाक मिसाइल को आसमान में ही नष्ट किया जा सके। अपनी विशाल आबादी की रक्षा के लिए भारत के पास यह सुरक्षा तंत्र होना ही चाहिए।

परीक्षण भी बहुत दिलचस्प ढंग से किया गया। पहले एक मिसाइल को दुश्मन की मिसाइल की तरह दागा गया और उसके बाद जमीन व समुद्र में तैनात भारतीय राडारों ने उस मिसाइल का तत्काल पता लगाया और चार मिनट के भीतर ही जमीन से जवाबी बैलिस्टिक मिसाइल ने उड़ान भरी और टारगेट से हवा में ऊपर ही जा टकराया। वैसे तो भारत कम दूरी, मध्यम दूरी और बहुत लंबी दूरी की मिसाइल बनाने में सक्षम है, पर आज के समय में मिसाइल बनाना जितना जरूरी है, उतना ही आवश्यक मिसाइलों से बचने की क्षमता विकसित करना भी है। इस परीक्षण में सबसे बड़ी सफलता दुश्मन की मिसाइल का पता लगाने की क्षमता है, जिसे साल 2006 से ही मुकम्मल करने की कोशिश में भारतीय वैज्ञानिक लगे हुए हैं। भारत अपने बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम के पहले चरण को पूरा कर चुका है, जबकि दूसरे चरण में नई श्रेणी के इंटरसेप्ट सिस्टम को पुख्ता करने का काम चल रहा है। कम दूरी की मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता भारत के पास पहले से ही है और अब 5,000 किलोमीटर दूर से आने वाली मिसाइलों को भी नष्ट करने की क्षमता भारतीय सेना की ताकत को नए मुकाम पर पहुंचा देगी।

कम दूरी की मिसाइलों का जवाब हमारे पास पहले से है और अब 5,000 किलोमीटर तक मारक क्षमता की मिसाइलों को भी नष्ट करने की क्षमता विकसित हो रही है।

चूंकि भारत की नीति कभी भी पहले हमला करने की नहीं रही है, इसलिए भी उसे मिसाइलों का जवाब देने में सक्षम होना चाहिए। आगे के लिए यह मानकर चलना चाहिए कि जब भी युद्ध होगा, भारत का मुकाबला मिसाइलों की बौछार से होगा, अतः उनसे सुरक्षा का कवच तैयार करना समय की मांग है। भारत ने एस-400 नाम का मिसाइल सुरक्षा कवच रूस से लिया है। अभी कुछ और की आपूर्ति होनी है। वास्तव में, हमें अपना पुख्ता मिसाइल सुरक्षा कवच विकसित करना चाहिए। ताजा सूचना है, युद्ध में लगा रूस अब भारत की जरूरतों पर भी ध्यान देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मास्को यात्रा के बाद रक्षा आपूर्ति में तेजी आ रही है। रूस हमें 120 मिसाइलें देने वाला है। ये सारी मिसाइलें हमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ठिकानों के आसपास तैनात करनी होंगी। बहरहाल, भारतीय रक्षा पंक्ति का भविष्य उज्ज्वल है और इसके लिए हमें पूरी तेजी से काम करना चाहिए।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 26 जुलाई, 1949

मजदूर कांग्रेस के प्रस्ताव

राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस मजदूर संगठन के क्षेत्र में देर से प्रविष्ट हुई, किंतु उसने अपना विशिष्ट स्थान बना लिया है। वह राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए मजदूरों की सेवा करने में संलग्न है। उसकी कार्यकारिणी की बैठक हाल में नई दिल्ली में हुई थी। उसने मजदूर संगठन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निश्चय किये हैं। उनमें एक निश्चय विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वह यह कि राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस खेत पर काम करने वाले मजदूरों के संगठन का काम अपने हाथ में लेगी। खेत-मजदूरों की ओर अभी तक किसी मजदूर संगठन ने ध्यान नहीं दिया, हालांकि उनकी संख्या १५ करोड़ के लगभग बताई जाती है। इसका यह कारण नहीं कि खेत-मजदूरों की दशा संतोषजनक है। वास्तविकता यह है कि उनकी दशा कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से अधिक गई-बीती है। जिस प्रकार जमींदार एक किसान की मेहनत का नतीजा स्वयं हड़प जाता है, उसी प्रकार किसान भी खेत-मजदूर का शोषण करता है और उसे अपनी मेहनत का बहुत थोड़ा मुआवजा मिलता है। जब तक जमीन का न्याययुक्त बंटवारा नहीं हो जाता और खेत-मजदूर खुद जमीन के मालिक नहीं हो जाते, तब तक उन्हें अर्थ-गुलामी की दशा में छोड़ना एक बड़े अन्याय को सहन करना होगा।

देहाती मजदूरों को संगठित करना आसान काम नहीं है। वे इतने दूर-दूर फैले हुए हैं कि उनका संगठन करने में भारी श्रम की आवश्यकता होगी। किंतु कोई भी काम मुश्किल हो, केवल इसीलिए उसे नहीं छोड़ा जा सकता। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ने जो यह निश्चय किया है, वह बुद्धिमत्तापूर्ण है कि वह देहाती मजदूरों का संगठन कांग्रेस कमेटियों की सहायता और सहयोग से करेगी। कांग्रेस कमेटियां पहले से देहात में काम कर रही हैं और इसलिए उनकी सहायता मूल्यवान सिद्ध हो सकेगी। मजदूर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देहाती मजदूरों को संगठित करने के कार्य में विशेष सावधानी और कौशल का परिचय देना होगा। उन्हें इस ढंग से काम करना चाहिए कि जिससे किसानों और देहाती मजदूरों के बीच कोई कटुता पैदा न हो। उनका लक्ष्य यह रहना चाहिये कि किसान स्वयं अपने मजदूरों के प्रति न्याय करने को प्ररित हो जायें। यदि किसान जमींदारों से न्याय की अपेक्षा रखता है, तो उसे अपने से निचली श्रेणी के लोगों के साथ न्याय करने को उद्यत होना चाहिए।

जब कारगिल से हमने दुश्मन को खदेड़ा

मोहन भण्डारी | लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड)

कारगिल युद्ध को 25 साल हो गए हैं। पाकिस्तान ने इसमें एक और करारी हार झेली थी। मैं इसके लिए भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रति श्रद्धा से शीश झुकाता हूं।

वह 7 मई, 1999 की दोपहर थी, जब नई दिल्ली स्थित मिलिट्री ऑपरेशन्स (एमओ) निदेशालय से मेरे डायरेक्टर का फोन आया और मुझसे कहा गया कि जैसे ही हम पालम उतरें, चीफ को लेकर सीधे ऑपरेशन रूम में पहुंच जाएं। उस वक्त मैं चीफ के साथ एक मिशन के लिए नाल-बीकानेर एयरफील्ड पर था। इस फोन की सूचना मैंने तुरंत चीफ को दी और करीब सात बजे हम एमओ निदेशालय पहुंच गए, जहां डीजीएमओ ने काली डंगरी पहने लोगों द्वारा घुसपैठ की खबर दी और बताया कि यल्दोर सब-सेक्टर में बंजू व कुकरथांग के पास हमारी सुरक्षा पंक्ति के सामने की चट्टानों से कुछ रेडियो एंटिना को बाहर निकले देखा गया है।

बाद में, जब कारगिल के सभी सब-सेक्टरों में घुसपैठ की सूचना आई, तो स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ ने एक सुनियोजित सैन्य कार्रवाई की है। जैसे-जैसे चीजें साफ होती गईं, यह भी पता चलने लगा कि इस दुस्साहस में पाकिस्तानी फौज की कुल 14 नियमित टुकड़ियां शामिल हैं। साथ ही, पाकिस्तानी तोप की 35 टुकड़ियां और अत्याधुनिक हथियारों का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। जाहिर है, आईबी और रॉ दुश्मन के इस दुस्साहस की भनक पाने में विफल रहे थे। ऑपरेशन रूम में सुरक्षा मामलों से जुड़ी कैबिनेट समिति की बैठक में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, जो होना था, हो गया, अब आगे की सुध लीजिए। लाहौर की अपनी ऐतिहासिक बस यात्रा के बाद वह पाकिस्तान द्वारा पीठ में इस तरह छुरा घोंपने से परेशान दिख रहे थे। बैठक समाप्त होते-होते मेरी टीम जवाबी योजनाएं बनाने में जुट गई। मैं कारगिल के लिए रवाना हो गया।

पाकिस्तान ने फ्रंटियर कॉर्प्स नॉर्दर्न आर्मी (एफसीएनए) के जवानों का इस्तेमाल किया था, जो यहां के हालात से वाकिफ थे। भारतीय सेना को भ्रमित करने के लिए कि यह घुसपैठ मुजाहिदीन द्वारा की गई है, कुछ आतंकियों ने पाकिस्तानी सिग्नल का इस्तेमाल करके बलती, शिना, दार्दी और कुछ अन्य स्थानीय बोलियों में बातें की थीं। वे शुरुआत में अपने मकसद में सफल भी हुए। मगर जल्द ही हमारी खुफिया एजेंसियों ने मुशर्रफ, जो तब चीन में थे और रावलपिंडी में मौजूद उनके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की टेलीफोन पर हुई एक बातचीत पकड़ ली, जिसमें वे दोनों कारगिल में पाक ऑपरेशन के बारे में चर्चा कर रहे थे। जाहिर है, इससे पाकिस्तान बेनकाब हो गया और पूरी दुनिया को पता चल गया कि भारतीय सीमा में दाखिल ये घुसपैठिए पाकिस्तानी सैनिक हैं, जो 12,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर तीन से नौ किलोमीटर तक अंदर आ चुके हैं। हालांकि, एक अन्य कैबिनेट बैठक में हमने यही फैसला लिया कि भारतीय सेना नियंत्रण रेखा पार नहीं करेगी, जिसकी प्रशंसा पूरी दुनिया ने की।

यल्दोर में भारतीय सीमा में करीब 300-350 पाकिस्तानी सैनिक आ गए थे, द्रास में 200-230, काकसर में लगभग 100 और मुश्कोह घाटी में 150-210। इस प्रकार उनकी कुल संख्या 900-950 थी। प्रधानमंत्री को बताया गया कि पहले द्रास से घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा, फिर बटालिक, काकसर और अंत में मुश्कोह से। पाकिस्तानी सेना का मकसद सबसे पहले छद्म युद्ध के लिए घाटी से रिजर्व भारतीय फौज को बुलाना था, फिर जोजी ला-लेह सड़क को काटना, तीसरा, दुष्प्रचार और मनोवैज्ञानिक दांव खेलना और चौथा, कश्मीर विवाद पर दुनिया का ध्यान खींचना।

अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में कोई आक्रामक अभियान चलाना एक बड़ी चुनौती होती है। हालांकि, काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड में सैनिकों की तैनाती वरदान साबित हुई, क्योंकि हमारे पास युद्ध के लिए जवान तैयार थे। कई जगहों पर और कई तरीकों से हमले की तैयारी की गई, क्योंकि इसमें दुश्मनों का संसाधन व ध्यान भटकाया जा सकता था और उनको अपनी कार्रवाइयों से चौंकाया जा सकता था। अलग-अलग दिशाओं से किया गया हमला प्वॉइंट 5140, टोलोलिंग, टाइगर हिल, प्वॉइंट 4875, स्टैंगबा और खालूबार रेंज में खासा सफल साबित हुआ। जूनियर लीडरशिप ने काफी बहादुरी दिखाई। तमाम स्तरों पर उच्च कमांडरों के साहसिक फैसलों और तोपखाने की भूमिका को भी कमतर नहीं माना जा सकता। वायु सेना ने तो अद्वितीय भूमिका निभाई। 23,000 फीट और उससे भी अधिक ऊंचाई पर स्थित दुश्मनों के बंकरों को निशाना बनाना उनकी दक्षता को दर्शाता है। मुन्थो ढालो स्थित प्रशासनिक व रसद बेस खत्म करने से दुश्मन के लड़ने की क्षमता काफी कम हो गई।

हमारे लिए भी प्रशासनिक जिम्मेदारी और रसद की नियमित आपूर्ति एक बड़ी चुनौती थी, जिसको हमारे सैनिकों ने तमाम मुश्किलों को झेलते हुए बनाए रखा। हताहतों को तेजी से वहां से हटाया जाता। जबकि, किसी पेशेवर सेना के विपरीत, पाकिस्तानी फौज अपने 249 मृतकों व घायलों को छोड़कर भाग खड़ी हुई। उसने केवल पांच शवों को स्वीकार किया, जिनमें टाइगर हिल पर मारे गए 12 एनएलआई बटालियन के कैप्टन करनाल शेर का शव भी शामिल था।

9 जुलाई को नवाज शरीफ को हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय से एक संदेश भेजा गया कि वह 11 जुलाई को वाघा बॉर्डर पर डीजीएमओ भेजें। हमारे डीजीएमओ के साथ मैं भी वहां गया और देखा कि मेजर जनरल तौकीर जिया (पाक डीजीएमओ) निःशब्द बैठे थे। इस बैठक में भारतीय डीजीएमओ ने स्पष्ट निर्देश दिया कि वे नियंत्रण रेखा से 100 मीटर पीछे हट जाएं और पीछे हटते समय सभी क्षेत्रों को साफ करें, बारूदी सुरंगें न बिछाएं। यह अगले 72 घंटों में पूरा किया जाना था, लेकिन अपनी आदत से मजबूर पाकिस्तानी फौज ने बात नहीं मानी। अब हमारे पास उन्हें खदेड़ने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था। अंततः 25 जुलाई की सुबह तक दुश्मन के सभी प्रतिरोधों को नाकाम करते हुए इलाके को साफ करा दिया गया। दोपहर तक प्रधानमंत्री को यह सूचना दी गई और फिर वाजपेयी साहब ने सद्भावना का परिचय देते हुए एकतरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। यदि पाकिस्तान ने भारतीय डीजीएमओ के निर्देशों का पालन किया होता, तो 16 या 17 जुलाई को ही युद्ध समाप्त हो गया होता।

ऑपरेशन विजय क्या था? एक युद्ध, एक क्लासिकल सीमित युद्ध, एक सशस्त्र संघर्ष या फिर कुछ और? आश्चर्य की बात थी कि दोनों सेनाएं भयंकर रूप से आमने-सामने थीं, लेकिन दोनों देशों में राजनयिक संबंध कायम थे। वैसे, पाकिस्तान के लिए सन् 1947-48 के जम्मू-कश्मीर युद्ध, साल 1965 और 1971 की जंग के बाद यह एक और करारी हार थी। मैं अपनी जीत के लिए भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रति श्रद्धा से शीश झुकाता हूं!

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

ओलंपिक में इस बार भारतीय खिलाड़ियों से बड़ी उम्मीदें

मनोज चतुर्वेदी | वरिष्ठ खेल पत्रकार

भारतीय खेलों में पिछले डेढ़ दशक में बहुत कुछ बदला है। अब खिलाड़ियों को प्रशिक्षण की बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं और विदेशी प्रशिक्षकों को लाने में धन की कमी भी आड़े नहीं आती। ऐसे में, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलने वाले ओलंपिक से भारतीयों की उम्मीदें बढ़ना स्वाभाविक है। 112 खिलाड़ियों वाला भारतीय दल बेहतर तैयारियों के साथ पेरिस ओलंपिक में भाग लेने गया है। भारतीय खिलाड़ियों की तैयारियों व पिछले प्रदर्शनों को देखकर लगता है कि हम टोक्यो ओलंपिक में किए एक स्वर्ण, दो रजत और चार कांस्य पदक वाले प्रदर्शन को सुधारने में सफल होंगे।

भारतीय खिलाड़ियों से इस बार दर्जनभर पदकों की उम्मीद की जा रही है। इन पदकों में यदि चार स्वर्ण भी जोड़ सकें, तो पिछले ओलंपिक में पदक तालिका में 48वें स्थान को टॉप 20 तक लाया जा सकता है। भारत को इस बार पिछले ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता जेवेलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, शटलर सात्विक साईराज, चिराग शेट्टी, पीवी सिंधु, बॉक्सर निकहत जरीन और महिला पहलवान अंतिम पंघाल से स्वर्ण की उम्मीद है। अगर ऐसा हो सका, तो यह प्रदर्शन भारतीय खेल इतिहास में मील का पत्थर साबित हो सकता है और इससे मिलने वाली प्रेरणा भारत को खेल शक्ति बनाने की तरफ ले जा सकती है।

भारतीय खिलाड़ियों से इस बार दर्जन भर पदकों की उम्मीद है। हम पदकों में यदि चार स्वर्ण जोड़ सके, तो शीर्ष 20 देशों में आ जाएंगे।

भारत को टोक्यो में एथलेटिक्स का पहला गोल्ड दिलाने वाले नीरज चोपड़ा इस साल बहुत प्रतियोगिताओं में नजर नहीं आए हैं, फिर भी वह दोहा डायमंड लीग में 88.36 मीटर जेवेलिन थ्रो का प्रदर्शन कर सके हैं और यह साल का चौथा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। वैसे भी इस साल दुनिया के ज्यादातर जेवेलिन थ्रोअर का प्रदर्शन 87 से 88 मीटर के बीच ही रहा है। यह सही है कि नीरज अब तक 90 मीटर की बाधा पार करने के सपने को पूरा नहीं कर पाए हैं, पर वह महत्वपूर्ण मौकों पर अपना बेस्ट देने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उनसे एक बार फिर सोने के तमगे के साथ लौटने की उम्मीद की जा सकती है।

एक अन्य भारतीय स्टार शटलर पीवी सिंधु काफी समय से पूरी रंगत में नहीं दिखी हैं, पर उनकी लय में लगातार सुधार होना उनको पदक का दावेदार बनाता है। वह यदि पेरिस में पदक जीतने में सफल रहीं, तो लगातार तीन ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगी। सिंधु को बड़े टूर्नामेंट का खिलाड़ी माना जाता है। वह जब तिरंगे की प्रतिष्ठा के लिए खेलती हैं, तो उनके खेल में एक अलग ही निखार आ जाता है। सिंधु ने जब 2016 के रियो ओलंपिक में पदक जीता था, तो उनका उस साल जीत-प्रतिशत 63 था और टोक्यो वाले साल 62.1 था। इस साल भी उनका जीत प्रतिशत 62.5 है। वैसे, बैडमिंटन में सिंधु से भी ज्यादा पदक की संभावनाएं सात्विक और चिराग की जोड़ी से है। यह जोड़ी इस समय विश्व में नंबर वन रैंकिंग पर रहकर पेरिस में भाग ले रही है। यह जोड़ी इस साल थाईलैंड ओपन के अलावा फ्रेंच ओपन का भी खिताब जीत चुकी है। ये दोनों खिलाड़ी ऐसा करिश्मा करने का माद्दा रखते हैं, जैसा पहले कोई भारतीय शटलर नहीं कर सका है। महिला मुक्केबाज निकहत जरीन और महिला पहलवान अंतिम पंघाल से भी सोने का तमगा जीतने की उम्मीद है। निकहत मौजूदा विश्व और कॉमनवेल्थ चैंपियन हैं। अंतिम पंघाल इस बार अकेली भारतीय पहलवान हैं, जिन्हें महिला फ्रीस्टाइल के 52 किग्रा वर्ग में चौथी सीडिंग मिली है। इसके कारण फाइनल से पहले उन्हें किसी दिग्गज का सामना नहीं करना होगा।

भारत ने टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में 41 साल बाद पदक जीता था। इस बार भारत के लिए लगातार दूसरे ओलंपिक में पोडियम पर चढ़ने की राह बहुत आसान नहीं है, पर यह असंभव भी नहीं है। अब देखने वाली बात है कि लंबे समय से टीम की सफलताओं में हाथ बंटाने वाले पीआर श्रीजेश को टीम पदक के साथ विदाई दे पाती है या नहीं? भारत के लिए वेटलिफ्टर मीराबाई चानू, महिला पहलवान विनेश फोगाट, टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना जैसे कई अन्य भी पदक के दावेदार हैं, पर भारत को दर्जन पार पदकों तक पहुंचना है, तो इसमें निशानेबाजों की भूमिका अहम रहने वाली है। देश उनसे उम्मीद लगाए हुए है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

सच्ची दृष्टि तभी मिलेगी

एक बूढ़ी आयरिश कैथोलिक महिला मृत्यु-शय्या पर लेटी थी। जब अंत करीब आ गया, तो उसके अंतिम संस्कार के बारे में आदेश देने के लिए फादर पैट्रिक को बुलाया गया। फादर ने वृद्धा का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, 'मेरी! क्या तुम जानती हो कि तुम अब कहां जा रही हो? जानती हो न?'

महिला ने कहा, 'जी धर्मपिता। जानती हूं।'

पादरी ने आगे कहा, 'तुम जीवन भर बहुत नेक रही, तुमने कोई पाप नहीं किया, प्रतिदिन प्रार्थना की और तुम एक धार्मिक महिला बनकर रही।' मेरी ने उत्तर दिया, 'धर्मपिता, आप ठीक कह रहे हैं; मैं हमेशा एक अच्छी कैथोलिक रही।' तब फादर पैट्रिक ने कहा, 'मेरी। तुमसे पूछने के लिए मेरे पास एक प्रश्न है। मैं जानना चाहता हूं कि तुम अपने ताबूत में सफेद लाइनिंग चाहती हो या बैंगनी?' मेरी ने पूछा, 'धर्मपिता! इनमें क्या फर्क है?'

फादर ने उत्तर दिया, 'यदि तुम वास्तव में एक नेक महिला बनकर रही हो, बहुत वासनायुक्त नहीं थी, तुमने कभी किसी से अवैध संबंध नहीं रखे, कभी चोरी नहीं की, कभी ईर्ष्यालु बनकर नहीं रही, कभी लालच नहीं किया, प्रभु के नाम का प्रयोग करते हुए कभी अभिमान या गर्व नहीं किया और एक अच्छी कैथोलिक बनकर रही, तब तुम्हारे ताबूत में सफेद लाइनिंग लगाई जाएगी। लेकिन यदि तुम वासनामय रही, तुमने अवैध संबंध स्थापित किए हैं, तुम लालची, घमंडी, ईर्ष्यालु रही, तुमने चोरी की, परमात्मा के नाम का प्रयोग गर्व से किया और एक बुरी कैथोलिक बनकर रही, तो तुम्हारे ताबूत में बैंगनी लाइनिंग होगी। अब मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि तुम अपने ताबूत में किस रंग की लाइनिंग चाहती हो?'

बूढ़ी मेरी ने अपनी आंखें बंद कीं, एक क्षण सोचा और फिर कहा, 'फिर ठीक है धर्मपिता। मैं चाहती हूं कि लाइनिंग सफेद रंग की ही हो, पर उसमें यहां-वहां थोड़े से बैंगनी रंग की भी झलक हो।'

तुम्हारी व्याख्याएं और अर्थ तुम्हारे मन के ही प्रतिबिंब बनने जा रहे हैं। तुम जो कुछ भी कहते हो, वही टकराकर वापस मुड़ता है। इसलिए जब कोई सद्गुरु तुम्हें कोई विधि दे, तो तुम्हें उसके बारे में सोच-विचार नहीं करना है, अन्यथा तुम उससे चूक जाओगे। चिंतन मार्ग से भटका देता है। तुम्हें उस पर ध्यान करना है और ध्यान का अर्थ चिंतन नहीं है, उसका प्रामाणिक अर्थ है खुद को होशपूर्ण बनाए रखना। तुम्हें वही बनाए रखना है, जिससे तुम उसे विस्मृत न कर दो। तुम शांत बैठते हुए, अपना होश बनाए रखते हुए, उसे कभी भूलो मत, बस सभी कुछ इतना ही है। और देर-सबेर कुछ चीजें तुम्हारे अंदर ही खिलेंगी और तुम्हें एक दृष्टि मिलेगी। वही दृष्टि उस विधि का अर्थ होगी। उस अर्थ को जानने के लिए तुम्हारे अंतरवार्तालाप को मिटना होगा।

फादर ने मृत्यु शय्या पर लेटी महिला से कहा, 'मेरी। तुमसे पूछने के लिए मेरे पास एक प्रश्न है। मैं जानना चाहता हूं कि तुम अपने ताबूत में सफेद लाइनिंग लगवाना चाहती हो या बैंगनी?'

ओशो

कमला हैरिस | अमेरिकी उप-राष्ट्रपति

इस (राष्ट्रपति) चुनाव में हम सबके सामने एक प्रश्न है: हम किस तरह के देश में रहना चाहते हैं? और इस क्षण की खूबसूरती यह है कि हममें से हर एक के पास इस सवाल का जवाब देने की ताकत है। सत्ता जनता के पास है।

बजट में भेदभाव के आरोप बेबुनियाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट पर भेदभाव का आरोप लग रहा है, जो गलत है। ऐसा लगता है कि विपक्ष द्वारा बिना बात ही सरकार की आलोचना करना या संसद में हंगामा खड़ा करना उसकी आदत सी बन गई है। बजट को जहां अर्थशास्त्री संतुलित बता रहे हैं, वहीं विपक्ष इसमें बिहार और आंध्र प्रदेश को खास तवज्जो देने का आरोप लगा रहा है। इन दोनों राज्यों के नाम पर इसलिए विरोध किया जा रहा है, क्योंकि यहां एनडीए की सरकार है और दोनों बड़े घटक दलों पर केंद्र की सत्ता टिकी है। मगर ऐसा करते हुए विपक्ष शायद यह भूल रहा है कि बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्यों में एक है और आंध्र प्रदेश को विभाजन के समय खुद कांग्रेस के नेतृत्व वाली तत्कालीन संप्रग सरकार ने विशेष सहायता देने का आश्वासन दिया था। ऐसी स्थिति में यदि विपक्ष मौजूदा सरकार पर भेदभाव का आरोप लगा रहा है, तो यह बहुत उचित नहीं जान पड़ता। विपक्ष द्वारा बजट का विरोध दरअसल वास्तविक मुद्दों पर चर्चा से बचने की एक चालाकी है।

मीना धानिया, टिप्पणीकार

अच्छी पहल

आम बजट का विरोध रहे विपक्षी दलों को उचित सलाह दी गई है कि प्रचार बटोरने के लिए विरोध की बेतुकी रस्म निभाने के बजाय वे पेश दस्तावेज को पूरा पढ़ें। आम बजट का कांग्रेस द्वारा विरोध किए जाने पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने यह कहकर भी चुटकी ली कि 70 साल तक 'पकौड़े' और 'जलेबी' खाए, तो पेट नहीं भरा। दरअसल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में आम बजट के बारे में कहा था कि सरकार इस बजट में गैर-भाजपा शासित प्रदेशों की थाली में पकौड़े और जलेबी तक नहीं दिए हैं। जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही है, उसको पता होना चाहिए कि बजट पेश करने के दौरान आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप देश के सभी राज्यों का नाम लें। कई योजनाओं में वे राज्य अप्रत्यक्ष तौर पर लाभान्वित होते हैं। स्पष्ट है, जिस तरह से विपक्षी दल बिहार और आंध्र प्रदेश के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, वह निंदनीय है। इन दोनों राज्यों को इसलिए मदद दी गई है, क्योंकि इनको इसकी जरूरत थी। मालूम हो कि बिहार आज भी सबसे पिछड़े और प्रति व्यक्ति न्यूनतम जीडीपी वाले राज्यों में एक है, जबकि आंध्र प्रदेश को अपनी राजधानी अमरावती को विकसित करना है। ऐसे में, विरोध करता विपक्ष जनता को भ्रमित करने का काम ही कर रहा है, जबकि बजट में कई अच्छी पहल की गई है।

युगल किशोर राही, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम
बजट में भेदभाव

सरकार बचाने की जुगत वाला बजट

विपक्षी दल यदि सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि बिहार और आंध्र प्रदेश का ही उसने ख्याल रखा है और बाकी राज्यों को छोड़ दिया है, तो कोई गलत नहीं जान पड़ता। पूरे आम बजट को देख लीजिए, जितनी सौगातें इन दोनों राज्यों को दी गई हैं, उतनी किसी अन्य प्रदेश को नहीं। वजह? क्योंकि, यहां ऐसे दलों की सरकार है, जिनकी मदद पर केंद्र सरकार टिकी है। मीडिया खबरों की मानें, तो यह 'मदद' इसी सूरत में दी गई थी कि इन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। चूंकि, आर्थिक सर्वेक्षण पेश करते हुए ही सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया था कि तकनीकी वजहों से बिहार विशेष राज्य का हकदार नहीं है, जबकि आंध्र प्रदेश को भी खाली हाथ रखा गया था। ऐसे में, इन दोनों दलों को संतुष्ट करने का एक ही मौका था कि बजट में इनके राज्यों पर खुलकर खजाना लुटाया जाए। यही किया गया और इन दोनों राज्यों को खुश करने की पूरी कोशिश की गई है।

आंकड़ों के मुताबिक, इन दोनों राज्यों को करीब 75 हजार करोड़ रुपये का पैकेज मिला है। बेशक, इन दोनों राज्यों को मदद मिलनी चाहिए, लेकिन यह मदद किसी अन्य राज्य की हकमारी पर नहीं होनी चाहिए थी। स्थिति यह है कि जिन राज्यों में लोकसभा चुनावों में राजग को उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिलीं, उन राज्यों को बजट के माध्यम से दंड दिया गया है, यानी उनको दरकिनार कर दिया गया है और बजट में उनके लिए कुछ नहीं रखा गया है। तर्क दिए जा रहे हैं कि सभी राज्यों के नाम बजट भाषण में नहीं लिए जा सकते। चलिए, यह तर्क मान लेते हैं, लेकिन जिन राज्यों को सरकार कुछ दे रही है (उसका तो दावा है कि सबको दे रही है), उसके नाम तो जाहिर करने ही चाहिए थे। यह क्या माना जा सकता है कि भारत जैसे लोकतंत्र में कोई पार्टी 'दान दो दरिया में डालो' के आधार पर काम करती है। यहां तो कोई पार्टी एक काम कर दे, तो वह उसका इतना प्रचार करती है, मानो उसने इतिहास ही पलट दिया है। ऐसे में, बजट का आवंटन किए जाने के बाद भी संबंधित राज्यों का नाम सार्वजनिक न करना चौंकाता ही है।

एक आदर्श बजट वही होता है, जिस पर कोई विवाद न हो, लेकिन इस बजट पर यह गंभीर आरोप लग रहा है कि अपनी सरकार बचाने के लिए बजट की सौदेबाजी की गई है। ऐसे आरोप किसी भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। सरकार को जल्द से जल्द वस्तुस्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सिर्फ आरोप को झुठलाने से काम नहीं चलेगा।

हिमांशु, टिप्पणीकार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। शुक्रवार, 26 जुलाई 2024

राज्यों की जीत

सुप्रीम कोर्ट ने माइंस एंड मिनरल्स (डिवेलपमेंट एंड रेग्युलेशन) यानी MMDR एक्ट, 1957 के तहत रॉयल्टी से जुड़े एक अहम मामले में फैसला दिया है कि इसे टैक्स नहीं माना जा सकता। इस फैसले के मुताबिक राज्यों को खनिज और खनिज वाली जमीनों पर केंद्र द्वारा ली जाने वाली रॉयल्टी के अतिरिक्त भी टैक्स लगाने का अधिकार है।

क्या है मतलब | केंद्र और राज्यों के अधिकारों से जुड़े इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1989 में दिए अपनी संविधान पीठ के फैसले को गलत करार दिया है। सात जजों की बेंच ने उस फैसले में खदान और खनिजों के विकास से जुड़े मामलों में टैक्स लगाने का अधिकार केंद्र का बताया था। स्वाभाविक ही, पहली नजर में नौ जजों की बेंच के बहुमत से दिए गए ताजा फैसले को केंद्र सरकार के लिए झटका बताया जा रहा है। लेकिन इस फैसले के निहितार्थ काफी दूर तक जाते हैं।

AI Image

रॉयल्टी : SC का बड़ा फैसला

आमदनी का नया स्रोत | जहां तक राज्य और केंद्र के अधिकारों की हदों का मामला है तो ताजा फैसला निश्चित रूप से कई राज्य सरकारों के लिए बड़ी राहत बन कर आया है। इस फैसले के कारण अब राज्य सरकारों को राजस्व का एक नया स्रोत मिल गया है। इससे जहां उनकी आमदनी बढ़ेगी, वहीं नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने और राज्य के विकास को तेज करने वाले कदम उठाने के मामले में केंद्र पर निर्भरता कम हो जाएगी। खासकर ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे खनिज संसाधनों से संपन्न राज्य इस मामले में ज्यादा फायदे की स्थिति में रह सकते हैं।

क्या होगा असर | सबसे बड़ा सवाल यह है कि विभिन्न राज्य सरकारें जब अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करने लगेंगी, तब उसका असर व्यवहार में किस तरह से सामने आएगा। इसका ठीक-ठीक अंदाजा तभी होगा, जब राज्य सरकारों के फैसले सामने आएंगे और लागू होने लगेंगे। फिर भी इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि विभिन्न राज्य अपनी जरूरतों के मुताबिक जो अतिरिक्त टैक्स लगाएंगे उससे तमाम खनिज पदार्थों की कीमतें बढ़ेंगी और इसका सीधा असर उन सभी उत्पादों की लागत पर पड़ेगा, जिनके उत्पादन में ये खनिज पदार्थ कच्चा माल के रूप में इस्तेमाल होते हैं।

संबंधों में संतुलन | अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून की व्याख्या करते हुए संविधान में निहित संघवाद की भावना को ध्यान में रखा है और राज्यों के अधिकारों को संरक्षित करने पर जोर दिया है। शुरुआती चुनौतियों के बावजूद उम्मीद की जानी चाहिए कि यह फैसला देश में केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को संतुलित करने में मददगार साबित होगा।

रोज़-ब-रोज़

क्यों नहीं आते

शैलेंद्र पांडेय

'विधायक जी आए हैं कभी?' टिकट देने के लिए बढ़ रहे कंडक्टर के हाथ बीच में ही रुक गए। कुछ वक्त लगा उसे सवाल की प्रासंगिकता को समझने में। और जब समझ आ गया कि बात निकली किस माहौल में है, तो जवाब में उसने एक चौड़ी मुस्कान बिखेर दी, 'अब कहां आएंगे!' ठीक ही कहा उसने, अब कहां ही आएंगे विधायक जी इस सिटी बस में। लेकिन, उनके नाम की सीट लाल रंग से मोटे-मोटे अक्षरों में लिखकर रिजर्व कर दी गई थी - माननीय विधायक/मंत्री। एक तो रंग खतरे वाला और ऊपर से इतने भारी-भरकम शब्द, उस सीट के प्रति एकदम से आदर भाव जाग गया। बैठने से पहले एक पल को लगा, अगर कहीं सचमुच अगले स्टॉप पर कोई विधायक या मंत्री अपने लाव-लश्कर के साथ चढ़ गए बस में तो? क्या माननीय इसी सीट पर बैठेंगे? लोगों के बैठते-बैठते गद्दी इतनी घिस गई थी कि अंदर से फोम बाहर झांक रहा था और रंग चीकट हो चला था। शीशों पर गर्द चढ़ी थी और सिटिंग गैप इतना कम था कि अगर कोई लंबे कद का विधायक आ जाता तो अडजस्ट ही नहीं हो पाता। थोड़ा टेढ़ा होना पड़ता उसको और इस चक्कर में वह दूसरे की सीट और जगह, दोनों मार जाता। वैसे ऐतराज तो इस बात पर भी हो सकता था कि केवल दो सीटें ही क्यों? कौन जनप्रतिनिधि दो की संख्या में चलता है भला और अगर चलता हुआ सामने आ भी गया तो बताइए कि उसे नेता कौन मानेगा, पहचानने से इनकार नहीं कर देंगे लोग? हालांकि लगता नहीं कि इस सब की नौबत कभी आई होगी। ऐसी किस्मत उस बस और उसमें सफर करने वालों की कहां। पहले कभी ऐसा होता होगा और जब होता होगा शायद तभी के दौर की याद में लखनऊ की उस सिटी बस में सीटों को विधायक के नाम कर दिया गया था।

लेकिन, कभी ऐसा होता तो था। बच्चन बाबा को अपने इलाके के विधायक तो ऐसे ही मिल जाते थे। उन्होंने ही बताई थी यह वाली कहानी, जब वह पढ़ाई के बाद बेरोजगार घूम रहे थे। बनारस के पिंडरा बाजार में रोडवेज बस स्टैंड पर ऐसे ही एक दिन उनसे टकरा गए इलाके के विधायक। 'अभी क्या हो रहा है?' विधायक ने पूछा। बाबा जो तब जवान थे, उनका जवाब आया, 'पढ़ाई पूरी हो गई है। अब नौकरी ढूंढ रहे।' लखनऊ की बस पकड़ने आए थे विधायक। यात्रा शुरू होने में कुछेक मिनट बाकी थे, उन्होंने तुरंत लेटर पैड निकाला और लिख दिया एक लेटर अपने दोस्त दूसरे विधायक के नाम, वहीं बस स्टैंड पर खड़े-खड़े। 'अब वाले किसी विधायक से मिले आप ऐसे?' बाबा जो तब पूरी तरह बाबा बन चुके थे, उन्होंने जवाब दिया, 'अब कहां मिलेंगे!' उन्होंने सिटी बस के कंडक्टर से बहुत पहले जवाब दे दिया था।

एकदा

अमृता के सपने

जिंदगी और मौत से जूझ रहीं अमृता चारपाई पर लेटे-लेटे ख्वाब देखा करतीं। वह सोचतीं, मेरे बाद यह कमरा मेरा म्यूजियम बनेगा। ये किताबें यहीं रहेंगी और मेरा बिस्तर भी इसी तरह रहेगा। साथ वाले कमरे में इमरोज की पेंटिंग अभी की तरह लटकती रहेगी। पिछला कमरा इमरोज का रहेगा। साथ वाले कमरे में मेरी लाइब्रेरी बन जाएगी। नाम होगा अमृता प्रीतम दा घर। घर के बाहर मेरी नेम प्लेट ऐसी ही रहेगी। उसके साथ इमरोज भी अपनी नेम प्लेट लगा सकता है। वह यहीं रहेगा, सभी आगंतुकों को मेरा म्यूजियम दिखाने के लिए। यह सब सोचते और कहते अमृता के लफ्जों में कल को लेकर कोई खौफ न था। आखिरकार वह वक्त आ गया। 31 अक्तूबर 2005 को अपने सारे ख्वाबों के साथ इमरोज को छोड़कर अमृता इस दुनिया से रुखसत हो गईं। लेकिन उनके सपने कभी पूरे न हुए। उनके बेटे शैली ने फौरन ही वह घर बेच दिया। उसकी नजर में इमरोज उसके परिवार का हिस्सा नहीं थे, तो उनसे मशविरा भी नहीं किया। बेटी कंदला अपने बच्चों के पास विलायत जा बसी थी। एक काबिल मां के बेटे के पास अपनी मां के लिए कोई ख्वाब न था, थी तो बस दौलत की चाह। शैली से इमरोज दौलत क्या मांगते, उन्होंने तो सारी जिंदगी अमृता के नाम कर दी थी। वह ग्रेटर कैलाश के एक छोटे-से घर में रहने लगे। उधर, शैली ने मकान बेचकर मिले रुपये कार में भरे और चला गया बंबई। शैली की इस नई दौलत को कुछ लोगों ने देख लिया। उन लोगों की नजर इस दौलत को हड़पने पर थी और एक दिन इसी चक्कर में शैली का मर्डर हो गया। अमृता और इमरोज की यादें लोगों के दिलों में अब भी जिंदा हैं, लेकिन शैली न मां का हुआ और न दुनिया का।

shital Verma

संकलन : **नाइस हसन**

पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ के 25 साल बाद पूर्वी लद्दाख में वैसी ही स्थिति का सामना कर रहा भारत

क्या करगिल का सबक़ याद रखा हमने

रंजीत कुमार

आज देश करगिल विजय की 25वीं सालगिरह मना रहा है। साल 1999 में इसी दिन हमारी सेना ने लद्दाख में करगिल की बर्फीली चोटियों पर जिहादी घुसपैठियों के भेष में जमे पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ भगाया था।

अमेरिका का दखल | परमाणु बमों से लैस भारत और पाकिस्तान के बीच कहीं खुला युद्ध न छिड़ जाए इस आशंका से घबराकर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने दखल दिया। उन्होंने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उस समय के पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ को वॉशिंगटन आमंत्रित किया था। वाजपेयी ने तो निमंत्रण स्वीकार नहीं किया, लेकिन पराजय का सामना कर रहे नवाज शरीफ अमेरिका पहुंच गए। 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस मनाता है, इसके बावजूद हालात की गंभीरता को देखते हुए क्लिंटन ने वाइट हाउस में नवाज शरीफ के साथ इसी दिन बैठक की और उन्हें पीछे हटने के लिए राजी किया।

सेना की वीरगाथा | पाकिस्तानी सेना को करगिल की चोटियों से बेदखल करने के लिए भारतीय सेना के 527 वीर सैनिकों ने अपनी कुर्बानी दी। कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज पांडेय, अजय आहूजा जैसे वीरों की कुर्बानियां प्रसिद्ध वीरगाथाओं में शुमार हो चुकी हैं। निश्चय ही पाकिस्तानी सेना करगिल में फंस चुकी थी और नवाज शरीफ को चेहरा छुपाने के लिए अमेरिकी बीच बचाव का बहाना चाहिए था।

साजिश भांपने में चूक | 90 के दशक में भारत आर्थिक तंगी से उबरने में लगा था। फिर, मई 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद उस पर कई तरह के अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगे थे। इसी बीच करगिल संकट आ गया। भारत का गुप्तचर तंत्र यह पता करने में विफल रहा कि पाकिस्तानी सेना कोई बड़ी साजिश रच रही है।

भारत की नाकामी | भारतीय राजनीतिक नेतृत्व भी इस गफलत में रहा कि परमाणु बमों से लैस भारत और पाकिस्तान के बीच अब पारंपरिक युद्ध नहीं छिड़ सकता। यहां तक कि प्रधानमंत्री वाजपेयी ने फरवरी 1999 में नवाज शरीफ के साथ शिखर बैठक करने के लिए लाहौर की प्रसिद्ध बस यात्रा की। अजीब बात यह कि उस वक्त पाकिस्तान के सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ करगिल घुसपैठ की तैयारी कर रहे थे।

एक और करगिल | तब भारत की सैन्य तैयारी न्यूनतम स्तर पर थी। आनन-फानन तोपों के गोले, लड़ाकू विमानों के लिए लेजर पॉड और सैन्य कलपुर्जे वगैरह विदेश से मंगाए गए। घुसपैठ के कुछ सप्ताह बाद ही पाकिस्तानी सेना पर दबाव बनाया जा सका। करगिल घुसपैठ का पता क्यों नहीं चला और पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ भगाने में दो महीने से अधिक का वक्त क्यों लगा, इसकी गहन समीक्षा के. सुब्रह्मण्यम की अध्यक्षता वाली कमिटी ने की थी।

File

LAC के पास चीनी घुसपैठ
- चीन के मामले में खुफिया तंत्र नाकाम
- भारतीय जमीन पर है चीन का कब्जा
- कूटनीतिक प्रयासों का कोई फल नहीं

पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ | उम्मीद थी कि करगिल से सबक लेकर भारत अपनी सीमाओं को इस तरह अभेद्य बनाएगा कि दोबारा ऐसे हालात पैदा नहीं होंगे। लेकिन विडंबना है कि पिछले चार बरसों से देश एक और करगिल का सामना कर रहा है। चीन पूर्वी लद्दाख की कई पहाड़ियों पर कब्जा जमाए बैठा है। पूर्वी लद्दाख की कुछ चोटियों को छोड़कर बाकी से चीनी सेना को पीछे जाने को भारत बाध्य नहीं कर सका है। इसके बारे में अब सभी मौन हो गए हैं।

दावे पर सवाल | दोनों देशों के बीच सैन्य तनातनी 5वें साल में प्रवेश कर गई है। गलवान घाटी, पैंगोंग, गोगरा और हॉट स्प्रिंग के भारतीय इलाके में बफर जोन बनवाकर चीनी सैनिक LAC तक पीछे लौट गए हैं, लेकिन देपसांग और देमचोक पर चीन का कब्जा बना हुआ है। इस बारे में कोई सवाल उठाया जाता है, तो देश के सुरक्षा कर्णधार काफी दृढ़ता से यह दावा करते हैं कि भारत ने अपनी एक इंच जमीन भी नहीं खोई है।

युद्ध का खतरा | मई 1999 में करगिल घुसपैठ की जब शुरुआती खबरें मिली थीं, तब इन्हें अफवाहें बताकर आला सैन्य जनरल कहते थे कि कुछ घुसपैठिये आए हैं, जिन्हें मार भगाया जाएगा। इसी तरह पूर्वी लद्दाख की भारतीय चोटियों पर चीनी सैनिकों ने अप्रैल 2020 के शुरू में ही डेरा जमा लिया था। आज भी वहां भारत और चीन के 50 हजार से अधिक सैनिक आमने-सामने तैनात हैं।

भारतीय दबाव बेअसर | चीनी सैनिक भारत की ओर से ऐसा दबाव नहीं महसूस कर रहे कि वे भारतीय दावे वाले इलाकों को छोड़ दें। 1999 में भारतीय सेना पाकिस्तान पर भारी पड़ी थी, लेकिन आज ढाई दशक बाद भारत चीनी सेना को बेदखल करने के लिए किसी तरह की सैन्य कार्रवाई करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। सैन्य कमांडरों और राजनयिक वार्ता के बीसियों दौर हो चुके हैं, लेकिन वार्ता की आड़ में चीन अपनी स्थिति और मजबूत ही करता जा रहा है।

मजबूरियां सामने आईं | चीनी घुसपैठ का पता लगाने में भी भारतीय गुप्तचर तंत्र नाकाम रहा। घुसपैठ के 6 महीने पहले ही चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अक्टूबर 2019 में चेन्नै में दूसरी अनौपचारिक शिखर बैठक की थी। करगिल घुसपैठ और आज के चीनी अतिक्रमण के पैटर्न में हम काफी समानता देखते हैं। चीनी कब्जे को पूरी तरह हटाया नहीं जा सका है और यह भारत की मजबूरियां उजागर करता है। सदी के मध्य तक महाशक्ति बनने का सपना देखने वाले भविष्य के भारत के लिए यह एक और बड़ा सबक है।

(लेखक रक्षा मामलों के जानकार हैं)

जंग के क़िस्से भी पगे हैं गंगा-जमुनी रस में!

कृष्ण प्रताप सिंह

लखनऊ की तहजीब को यों ही लाजवाब नहीं कहा जाता। उसकी लड़ाइयों के किस्से तक गंगा-जमुनी तहजीब में सराबोर दिखते हैं। इससे भी बड़ी बात यह कि वक्त बदल जाने और जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज हो जाने के बावजूद उसने इन किस्सों को भुलाया नहीं है। उसकी धरती पर किस्सागोई अब भी एक कला है, जिसके तहत किस्सागो कहीं भी अपने कद्रदानों को फुरसत के पलों में ऐसे किस्से सुनाते मिल जाते हैं।

लड़ाइयों के गंगा-जमुनी किस्सों में एक नवाब सफदरजंग (19 मार्च, 1739 - 05 अक्टूबर, 1754) के राजेंद्र गोसाईं नामक एक सिपहसालार से जुड़ा है, जो किस्सा कम और वाकया ज्यादा है। 1750 में नवाब की सेना में नियुक्ति पाने से पहले राजेंद्र गोसाईं मराठों के जागीरदार हुआ करते थे और संन्यासियों जैसे वेश व सामंतों जैसी चाल-ढाल के लिए जाने जाते थे। उनकी एक पहचान अपने गुमान की रक्षा के लिए हद से गुजर जाने वाले अजीबोगरीब शख्स की भी थी।

मराठों ने उन्हें झांसी के मोंठ नामक गांव की जागीर दे रखी थी। अपने प्रभुत्व के प्रदर्शन के लिए उन्होंने उस गांव में पहले एक आलीशान गढ़ बनवाया, फिर आसपास के कई गांवों पर जबरन कब्जा कर उन पर अपना रौब गालिब करने लगे। उनकी बदगुमानियां नाकाबिल-ए-बर्दाश्त हो गईं तो मराठों ने न सिर्फ मोंठ गांव की जागीर वापस ले ली, बल्कि बलपूर्वक उन्हें उस क्षेत्र से ही निकाल बाहर किया।

बेबसी के उन दिनों में गोसाईं अपने लाव-लश्कर के साथ इधर-उधर फिर रहे थे कि उन्हें पता चला, नवाब सफदरजंग इलाहाबाद के पास हो रही एक लड़ाई में दुश्मनों से घिर गए हैं। फिर क्या था, इसे सुनहरा अवसर मानकर वह अपने लश्कर के साथ लड़ाई की जगह पहुंच सफदरजंग की मदद में लग गए। उनके सैनिकों को वहां की परिस्थिति के अनुसार दुश्मनों पर भारी पड़ने के कई नए गुर भी सिखाए।

उनकी बदौलत सफदरजंग घेरा तोड़ने में सफल हुए तो उनको अपना सिपहसालार बनाने की इच्छा जताई। इस पर गोसाईं ने उनके सामने दो शर्तें रखीं। पहली, उन पर रोज-रोज नवाब को सलाम करने की बंदिश न हो और दूसरी, उन्हें अपने नक्कारे बजाने के लिए अनुमति न लेनी पड़े। वह अपनी मर्जी से नक्कारे बजाते इधर-उधर, जहां जी चाहे फिरा करेंगे। सफदरजंग ने उनकी दोनों शर्तें मान लीं। फिर तो गोसाईं ने भी उनके प्रति वफादारी की इंतिहा कर दी।

AI Image

अवधनामा

कई लड़ाइयों में तो उनके लिए जान की बाजी तक लगा दी। 14 जून, 1753 को हुई एक भीषण लड़ाई में एक दुश्मन की गोली से वह वीरगति को प्राप्त हुए तो सफदरजंग को लगा कि उनका दाहिना हाथ टूट गया है। नवाब ने लड़ाई रोककर दस दिनों तक गोसाईं की मौत का शोक मनाया। उनके दो शिष्यों को अपनी सेना में ऊंचे ओहदे और उपाधियां वगैरह भी दीं।

एक और किस्सा रूहेलखंड के पठान शासकों के विरुद्ध 'रामछतौनी के रण' का है। इस रण में एक पीढ़ी पहले फैजाबाद के दीवान रहे आत्माराम के पौत्र जगतनारायण भी सफदरजंग के साथ थे। लड़ाई शुरू हुई तो पठानों के दोतरफा हमले से सफदरजंग की सेना में खलबली मच गई। एक गोली खुद सफदरजंग के जबड़े में आ लगी, जिससे गहरा घाव हो गया और वह बेहोश होकर अपने हाथी के हौदे में लुढ़क गए। गनीमत थी कि पठान सैनिक हौदे को खाली समझ उन्हें तलाशने दूसरी तरफ चले गए। उन्हें पकड़ नहीं पाए। पकड़ पाते तो जाने उनका क्या हाल कर डालते!

किस्से के मुताबिक जगतनारायण ने मौके की नजाकत समझी और अपने घोड़े से कूदकर सफदरजंग के हाथी पर जा चढ़े। जैसे-तैसे उनके जबड़े से खून बहना रोका और कुशल महावत की भूमिका निभाते हुए उन्हें युद्धभूमि से सुरक्षित बाहर निकाल लाए। मरहम-पट्टी के बाद सफदरजंग की बेहोशी टूटी तो जगतनारायण उन्हें नवाब बेगम के नाम से प्रसिद्ध उनकी बेगम सदरुन्निशां उर्फ सदरजहां के पास ले गए। सफदरजंग की हालत देखकर बेगम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने नवाब की जान की सलामती के लिए खुदा का शुक्रिया अदा किया और जगतनारायण को अपना भाई बनाकर उन पर इनामों व इनायतों की बारिश कर दी।

विशुद्ध राजनीति

पॉलिटॉक

पीके की पार्टी का असर

इन दिनों बिहार में प्रशांत किशोर की पार्टी और उस पर RJD की प्रतिक्रिया वहां बहुत चर्चा में है। प्रशांत किशोर ने पिछले दो वर्षों तक काम करने के बाद इस साल 2 अक्तूबर को अपनी पार्टी लॉन्च करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वह अगले साल विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करेंगे। इसके तुरंत बाद RJD के प्रदेश अध्यक्ष ने एक दिलचस्प पत्र जारी किया। इसमें उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि उनके दल के कई नेता और कार्यकर्ता, प्रशांत किशोर की पार्टी से जुड़ रहे हैं। उन्होंने इसे पार्टी विरोधी काम घोषित किया है। इस पत्र को लेकर पार्टी के अंदर तीखी प्रतिक्रिया भी हुई कि इससे पीके को ही लाभ हुआ। लेकिन इसके कुछ दिन बाद एक और लेटर निकाला गया, जिसमें एक स्थानीय नेता को प्रशांत किशोर की पार्टी से जुड़ने के कारण RJD से निष्कासित करने का आदेश जारी किया गया। RJD की इस प्रतिक्रिया से प्रशांत किशोर और उनके लोग बहुत खुश हैं। उनका मानना है कि इससे उन्हें जरूरी चर्चा मिल रही है और वे यह संदेश देने में सफल हो गए कि उन्होंने राज्य की सियासत में अपनी जगह बना ली है। पिछले कुछ दिनों में तमाम दलों के नेता उनके साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि वह RJD से अधिक मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देंगे।

ओडिशा के बाद किसकी बारी

कांग्रेस ने एक हैरान करने वाले कदम में अपनी ओडिशा इकाई को भंग कर दिया। पार्टी ने कहा है कि अब वहां नए सिरे से संगठन गठित किया जाएगा। पार्टी ने प्रदेश, जिला और ब्लॉक इकाइयों के साथ-साथ यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई सहित सभी संगठनों को भंग कर दिया है। कांग्रेस को फीडबैक मिला था कि वहां संगठन के अधिकतर नेताओं ने सत्तारूढ़ BJP और दूसरी पार्टियों के साथ समझौता कर रखा है। अब इसके बाद पूछा जाने लगा है कि क्या कांग्रेस ऐसा ही कदम दूसरे राज्यों में भी उठाएगी। सूत्र बता रहे हैं कि कम से कम दो और राज्यों में कांग्रेस ऐसी ही कार्रवाई कर सकती है। इसमें सबसे अहम है मध्य प्रदेश। वहां भी पिछले कुछ बरसों में पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई है। विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद आम चुनाव में भी उसे राज्य की सभी 29 लोकसभा सीटों पर मुंह की खानी पड़ी। वहां भी पार्टी नेताओं के दूसरे दलों द्वारा 'मैनेज' होने की शिकायतें मिलती रही हैं।

बदल गई रणनीति

संसद के बजट सत्र में विपक्ष ने इस बार अपनी रणनीति में अचानक बदलाव कर लिया। पहले दिन सरकार को लग रहा था कि विपक्ष हंगामा करेगा, जिससे शायद कार्यवाही नहीं चल पाएगी। विपक्ष ने भी एक दिन पहले तमाम मुद्दों पर हंगामा करने का संकेत दिया था। लेकिन सत्र के पहले दिन वह सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेता दिखा। खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में NEET का मुद्दा उठा दिया, जिसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हस्तक्षेप करते हुए जवाब देना पड़ा। विपक्ष को अचानक लगा कि अगर वे हंगामा करते हैं और उसकी वजह से सदन नहीं चलता, तो सरकार को ही लाभ होगा। विपक्ष का यह भी मानना है कि अभी कई ऐसे मुद्दे हैं जहां सरकार को घेरा जा सकता है। इस बार सदन में उसके पास संख्या बल भी इतना है कि सरकार उनकी अनसुनी नहीं कर पाएगी। इसलिए सदन में हंगामा करने के बजाय वे मुद्दों के जरिए सरकार पर हमला करने की रणनीति के साथ उतरे। वैसे भी सदन में हंगामा करने के सवाल पर विपक्ष में एक राय नहीं रहती थी। कई नेता मुद्दे उठाने के पक्ष में दिखाई देते थे।

ख़बर कौन प्लांट कर रहा

पिछले दिनों उत्तर प्रदेश BJP में उठापठक को लेकर खबरें लगातार चर्चा में रहीं। लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर समीक्षा का दौर चल रहा था। पार्टी के दो भागों में बंटने के संकेत मिले। इससे निबटने के लिए शीर्ष नेतृत्व ने हस्तक्षेप किया। नेतृत्व ने इस बार दोनों पक्षों से पूछा कि आपसी लड़ाई की खबरें कौन प्लांट करा रहा है। दरअसल पार्टी के दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर परोक्ष वार किए। लेकिन शीर्ष नेतृत्व के इस संकेत के बाद कि इस हरकत के लिए दोनों पक्षों को नुकसान उठाना पड़ सकता है, बयानबाजी बंद हुई। हालांकि इसे तूफान से पहले की शांति भी कहा जा रहा है। प्रदेश के नेताओं का एक वर्ग अब भी नाराज है। वह पार्टी नेतृत्व से निर्णायक हस्तक्षेप की मांग कर रहा है। दूसरे वर्ग का कहना है कि किसी तरह के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। वहीं पार्टी नेतृत्व अभी महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश का मुद्दा फिलहाल ठंडे बस्ते में डालने के मूड में है।

AI Image

बनने लगा दबाव

लोकसभा चुनाव परिणाम का असर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर दिखने लगा है। सहयोगी दलों के नेता एकनाथ शिंदे और अजित पवार अभी से BJP पर अधिक सीट का दबाव बनाने लगे हैं। दोनों नेता BJP से न सिर्फ अपने दलों के लिए अधिक सीटें मांग रहे हैं बल्कि वे अपनी-अपनी सीटों का चयन कर वहां चुनाव प्रचार में भी जुट गए हैं। इन नेताओं का आकलन है कि लोकसभा चुनाव के बाद BJP अपनी शर्त नहीं थोप सकती है और आज की तारीख में वे सौदेबाजी कर अधिक लाभ हासिल करने की स्थिति में हैं। एकनाथ शिंदे तो BJP पर यह दबाव भी बना रहे हैं कि उन्हें NDA का सीएम उम्मीदवार घोषित किया जाए। दोनों नेताओं ने प्रभावी चुनाव प्रचार सुनिश्चित करने के लिए अलग से बड़ी प्रचार एजेंसी की मदद भी ले रखी है।

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ भरोसा न टूटे

यह पत्र 25 जुलाई के संपादकीय 'क्लीन चिट नहीं' से संबंधित है। विवादों में रही NEET-UG परीक्षा पर सुप्रीम फैसला कई सवालों का जवाब है। इस तरह की परीक्षाओं में स्टूडेंट्स जी-जान लगाकर तैयारी करते हैं। कई स्टूडेंट्स तीन-चार टर्म एग्जाम देते हैं। ऐसे में अगर पेपर लीक जैसे मामले आते हैं, तो उनका भरोसा ही व्यवस्था से उठ जाएगा। पेपर लीक एक गंभीर समस्या है, जो शिक्षा प्रणाली की साख को कमजोर करता है। यह न केवल स्टूडेंट्स के समय और मेहनत को बर्बाद करता है, बल्कि प्रशासन पर भी अतिरिक्त बोझ डालता है। इस समस्या के समाधान के लिए सख्त निगरानी और तकनीकी उपायों की आवश्यकता है।

सुनीता गुप्ता, ईमेल से

■ रोज़गार बढ़े

24 जुलाई का संपादकीय 'युवा शक्ति का खयाल' पढ़ा। इस बार के बजट में सरकार के 10 साल के अनुभव की स्पष्ट झलक दिखाई देती है, जहां बड़े सुधारों की घोषणा से बचते हुए राज्यों को साथ लेकर चलने पर जोर दिया गया है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि राज्य जब तक केंद्र के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, देश के विकास का सपना पूरा नहीं हो सकता। यह स्वीकार किया गया है कि सरकारी नौकरियों की संख्या बढ़ाना संभव नहीं है, इसलिए निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सकारात्मक पहल की गई है।

सुरेंद्र रावत, ईमेल से

■ आतंकियों पर शिकंजा

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हुए आतंकी हमले ने एक बार फिर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति की गंभीरता को उजागर किया है। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला किया। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इस घटना को गंभीरता से ले रही हैं और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का संकल्प ले चुकी हैं। कुपवाड़ा का यह आतंकी हमला इस बात की याद दिलाता है कि आतंकवादियों का नेटवर्क अब भी सक्रिय है और रणनीतिक कार्रवाई जरूरी है।

प्रतीक गोयल, साहिबाबाद

nbtedit@timesgroup.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

बाइडन बाहर हुए तो ट्रंप पर भारी पड़ीं हैरिस - एक खबर

- राजनीति का पलड़ा है भाई, कभी भी भारी-हल्का हो सकता !

कविता सिंह

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

hindi.speakingtree.in

रील के चक्कर में रियल लाइफ को ही भूल गए हम

बी.के. शर्मा

हम सभी का अनुभव है कि अगर मनुष्य कोई काम पूरी एकाग्रता और स्थिरता से करता है, तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इस समय के भागदौड़ भरे जीवन में हर उम्र के बच्चे, विद्यार्थी, युवक समर्पण के अभाव में जीते हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण है मन और इंद्रियों के संयम का अभाव। इन हालात में वे कर्तव्य परायणता का भाव नहीं रख पाते। आधे-अधूरे मन के साथ अपने काम को किसी तरह पूरा करने में लगे रहते हैं। नतीजतन, काम में अपूर्णता। साथ ही, मन अशांत और दुखी हो जाता है।

हमारे मन और इंद्रियों के एकाग्र न होने का एक प्रमुख कारण है स्मार्टफोन का हद से अधिक उपयोग। हर थोड़ी देर में मोबाइल देखना हम सभी की आदत बन चुकी है। कोई कॉल न आया हो, कोई मेसेज न हो, तब भी हम बार-बार वट्सऐप और दूसरे सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म चेक करते रहते हैं। इससे हमारे मन में इतनी चीजें या गैर जरूरी जानकारी प्रवेश कर जाती है कि ध्यान भटकने लगता है। एक विषय पर मन स्थिर नहीं रहता, चंचल और विचलित हो जाता है। इसी वजह से अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पाते। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आज के दौर में मोबाइल बहुत ही जरूरी है। यह अपडेट रखता है और जानकारी पाने का प्रमुख टूल है। इंफॉर्मेशन और नॉलेज के लिए यह उसी तरह से जरूरी है, जैसे स्वस्थ रहने के लिए भोजन। लेकिन अगर भोजन करते समय किसी चीज का स्वाद आ जाता है तो जबान उस पर आसक्त हो जाती है। मन उस स्वाद में रम जाता है, उससे बाहर नहीं निकलना चाहता। इसी प्रकार अधिक समय तक मोबाइल का उपयोग करने से हमारा मन उसमें आसक्त हो जाता है। यह अकेला मन ही हमारी बुद्धि को हर लेता है और हमारे अंदर कर्तव्य परायणता न होकर मोबाइल में ही सुख बुद्धि पैदा हो जाती है। किसी तीर्थ यात्रा में भी जाते हैं, तो वहां पूरे मन से देवी-देवता के दर्शन करने के बजाय फोटो खींचने, रील बनाने और स्टेटस अपडेट करने में ही व्यस्त रहते हैं। उस तीर्थ के दर्शन से आनंद और मानसिक शांति की अनुभूति हासिल करने के बजाय हम मोबाइल पर वक्त जाया कर देते हैं। इस चक्कर में कभी-कभी दूसरों के उपहास का पात्र बनते हैं।

मोबाइल फोन के उपयोग के गुण-दोष पर विचार करें। अगर इसका समयबद्ध और सही इस्तेमाल किया जाए तो यह बेहद जरूरी है। जिस प्रकार अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत, उपवास और मौन आदि की आवश्यकता है, उसी प्रकार से सप्ताह में एक दिन के लिए हमें मोबाइल उपवास रखने के विषय में भी विचार करना चाहिए। उस दिन हम केवल बहुत ही जरूरी कॉल तक खुद को सीमित कर लें, अगर कोई इमरजेंसी हो तो ही फोन उठाएं वरना प्रण करें कि उसे छुएंगे भी नहीं। शुरू में इस तरह के उपवास को रखने में कुछ बेचैनी का अनुभव होगा, लेकिन फिर इसका लाभ दिखने लगेगा। मानसिक शांति और एकाग्रता आएगी तो मोबाइल का कम इस्तेमाल अपने आप आदत में शुमार हो जाएगा। एकाग्रता के साथ अपना काम करने के कारण हम एक प्रकार की शांति और सुख का अनुभव कर पाएंगे।

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्सः 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु.; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)